हिन्दी प्रादेशिक समाचार
आकाशवाणी चंडीगढ़
(तिथि 19 मार्च 2025, समय 1810 (10 मिनट)

- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में हरियाणा पुलिस में 20 इंस्पैक्टरों की भर्ती को लेकर उच्च न्यायालय के फैसले पर महाविधवक्ता की राय ली जाएगी।

- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "मेरा पानी मेरी विरासत योजना " के तहत धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों को अपनाने के लिए किसानों को8000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

- सरकार ने नारनौंद में बाई-पास के निर्माण के लिए 1825 लाख 43 हजार रुपये मंजूर किए।

- भिवानी स्थित हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने शैक्षिक सत्र में 9 वीं से 12 वीं कक्षा के विस्तृत पाठ्यक्रम मूल्यांकन योजना और प्रश्न पत्र तैयार करने को लेकर विषय विशेषज्ञों से विचार साझा किए।

****

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कांग्रेस कार्यकाल में हरियाणा पुलिस में 20 इंस्पैक्टरों की भर्ती को लेकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले के सम्बन्ध में महाविधवक्ता की राय ली जाएगी।मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा में शून्यकाल में इस भर्ती प्रक्रिया पर उठाए गए मुद्दे पर सदन में बोल रहे थे।उन्होंने कहा कि यदि न्यायालय के

निर्णय की अनुपालना में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग मामले की जांच किसी विशेष एजेंसी से करवा सकता है तो सरकार उन्हें तुरंत सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए तैयार है।

सी एम -ए

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में सरकारी नौकरी में भर्ती प्रक्रिया ठीक नहीं थी। उस समय योग्य युवाओं के साथ अन्याय होता रहा।

****

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसान हित में जितने निर्णय पिछले 10 वर्षों में वर्तमान केन्द्र व राज्य सरकार ने लिए हैं उतने पहले की सरकारों ने कभी नहीं लिए। उन्होंने कहा कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलों को अपनाने के लिए किसानों को अब 8000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो पहले 7000 रुपये प्रति एकड़ थी। इतना ही नहीं, किसानों को सहकारी बैंकों से जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।मुख्यमंत्री आज विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल द्वारा प्रदेश के किसानों पर फसली ऋण के बारे पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में बोल रहे थे।उन्होंने सदन को अवगत करवाया कि हरको बैंक व अन्य सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को फसली ऋण 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर दिया जाता है, परंतु यह ब्याज की राशि 4 प्रतिशत हरियाणा सरकार द्वारा तथा 3 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है।

सीएम-बी

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा किसान हित में निरंतर लिए जा रहे निर्णयों के फलस्वरूप पिछले 10 वर्षों में किसान की आय में भी अभूतपूर्व वृद्धि

हुई है।उन्हें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से सब्सिडी देकर टपकन व फव्वारा सिंचाई प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके अलावा, 10 वर्षों में पहली बार सिंचाई के लिए अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने का काम वर्तमान सरकार द्वारा किया जा रहा है।

****

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ऑनलाइन गेम और सट्टेबाजी की गतिविधियों से निपटने में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, पिछले साल एक हजार 97 सट्टेबाजी और ऑनलाइन गेम वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाया गया था। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ऐसी गतिविधियों से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों दोनों को मिलकर काम करना होगा और साइबर अपराध से जुड़ी सभी एजेंसियां तालमेल के साथ काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि साइबर दुनिया के नकारात्मक प्रभावों के बारे में समाज में जागरूकता आ रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट और टेलीकॉम एक्ट जैसे हाल ही में पारित कानूनों के साथ एक अच्छा □ांचा तैयार किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि जब भी उल्लंघन का कोई मामला सरकार के संज्ञान में आता है, तो संवैधानिक □ांचे के भीतर कार्रवाई की जाती है।

****

प्रादेशिक सामाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं।

हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग- इन कर सकते हैं।

यह समाचार हमारे यू- ट्यूब चैनल और एक्स हैंडल Akashvani News Chandigarh पर भी उपलब्ध हैं।

****

हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने बताया कि सरकार ने नारनौंद में बाई-पास निर्माण के लिए 1825 लाख 43 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।श्री रणबीर गंगवा आज विधानसभा में नारनौंद के विधायक जस्सी पेटवाड़ द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। श्री गंगवा ने बताया कि नारनौंद कस्बे के लिए 4किलोमीटर 47 मीटर लंबा नया बाईपास बनाने का प्रस्ताव था । उन्होंने सदन को यह भी बताया कि नारनौंद में बाई-पास निर्माण के लिए ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से भूमि क्रय का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

****

भिवानी स्थित हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं के विस्तृत पाठ्यक्रम, प्रश्न-पत्र डिजाइन, सैंपल प्रश्न -पत्र एवं विस्तृत मूल्यांकन योजना को तैयार करने के लिए आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

बोर्ड के अध्यक्ष प्रो. डा. पवन कुमार ने बताया कि इस कार्यशाला में शिक्षा जगत से जुड़े विभिन्न विषयों सामाजिक विज्ञान, इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन व भूगोल के विषय विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए।

डा. पवन कुमार-20 सेकंड

इस दौरान बोर्ड अध्यक्ष ने पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप ढ़ालने के लिए विषय विशेषज्ञों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि जब तक अध्यापक द्वारा करवाया जा रहा अध्यापन विद्यार्थी के मन मस्तिष्क में नहीं बैठता, विषय वस्तु को सरलता से नहीं समझा जा सकता। बोर्ड स्तर पर इसके लिए विस्तृत मंथन किया गया है। उन्होंने कहा

डा. पवन कुमार-37 सेकंड

उन्होंने कहा कि बोर्ड बच्चों को गुणात्मक शिक्षा देने के लिए सकारात्मक कदम उठा रहा है। पठन-पाठन की क्रिया को और अधिक तर्कशील और सरल बनाया जा रहा है।

****

किसानों की मांगों को लेकर केंद्र सरकार ने आज चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) से जुड़े किसान नेताओं के साथ बैठक की।किसानों के साथ सातवें दौर की बैठक के बाद केन्द्रीय मंत्री शिव राज चौहान ने कहा कि बैठक सकारात्मक माहौल में हुई, अगली बैठक 4 मई को होगी।पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीम ने भी कहा कि बैठक सकारात्मक माहौल में हुई। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी को आगे की बातचीत के लिए तैनात किया गया है। क्योंकि यह बातचीत देश के सभी किसानों से जुड़ी है।

****

भिवानी में नैफेड और आढ़तियों में सहमति न बन पाने के कारण सरसों की खरीद अब तक शुरू नहीं हो पाई है। भिवानी से हमारे सवांददाता ने बताया है कि आढ़ती नैफेड द्वारा 25-25 लाख रूपये की सिक्योरिटी जमा करवाने की सरत को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान भुरू ने बताया कि 95 फीसदी आढ़ती सिक्योरिटी देने में सक्षम नहीं है तो 6-6 महीने तक सिक्योरिटी वापिस न मिलने के कारण आढ़तियों को आय से अधिक ब्याज देना प□ता है , उन्होंने कहा कि वे समस्या के समाधान के लिए कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा से मुलाकात करेंगे वहीँ भिवानी मंडी समिति के सचिव अनिल कुमार ने कहा की उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है हर साल खरीद सीजन की शुरुआत में यह समस्या आती है जैसे सरसों की आवक होने लगेगी एजेंसी आढ़तियों से बातचीत कर कोई समाधान निकल लेगी।